



संविधान का निर्माण

संविधान सभा की मांग

- 1934 - एम एन राय द्वारा
- 1935 - कांग्रेस द्वारा
- 1936 - लखनऊ अधिवेशन में जे.एल.नेहरू द्वारा
- 1940 - लिनलिथगो द्वारा अगस्त ऑफर
- 1940 - संविधान सभा की मांग मान ली गई
- 1940 - लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया

कैबिनेट मिशन योजना

- 9 दिसंबर 1946 - प्रथम बैठक - 211 सदस्य
- 13 दिसंबर 1946 - जेएल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प
- 22 जनवरी 1947 - उद्देश्य संकल्प अपनाया गया
- 22 जनवरी 1947 - समिति - 8 प्रमुख और 13 लघु

संविधान सभा

- संघ शक्ति समिति - जवाहर लाल नेहरू
- प्रक्रिया समिति के नियम - डॉ राजेंद्र प्रसाद
- प्रान्तीय संविधान समिति - सरदार पटेल
- संचालन समिति - डॉ राजेंद्र प्रसाद
- मसौदा समिति - डॉ० बी.आर. अम्बेडकर
- मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति - सरदार पटेल
- संघ संविधान समिति - जवाहर लाल नेहरू
- राज्य समिति - जवाहर लाल नेहरू

समिति

- संविधान सभा के कार्यों पर समिति - जी.वी मावलंकर
- नागरिकता पर तदर्थ समिति - एस वरंचरी
- प्रेस गैलरी समिति - उषा नाथ सेन
- क्रेडेंटिअल समिति - अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
- व्यवसाय समिति का आदेश - डॉ के-एम. मुंशी
- वित्त एवं कर्मचारी समिति - डॉ राजेंद्र प्रसाद
- मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर समिति - बी. पट्टाभि सीतारमैया
- सदन समिति - बी. पट्टाभि सीतारमैया
- सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति - एस वरदाचारी
- वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति - नलिनी रंजन सरकार
- संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति - जवाहर लाल नेहरू
- भाषाई प्रांतों पर आयोग - एस.के. डार
- राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति - डॉ राजेंद्र प्रसाद

गौण (लघु)

- संविधान सभा के कार्यों पर समिति - जी.वी मावलंकर
- नागरिकता पर तदर्थ समिति - एस वरंचरी
- प्रेस गैलरी समिति - उषा नाथ सेन
- क्रेडेंटिअल समिति - अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
- व्यवसाय समिति का आदेश - डॉ के-एम. मुंशी
- वित्त एवं कर्मचारी समिति - डॉ राजेंद्र प्रसाद
- मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर समिति - बी. पट्टाभि सीतारमैया
- सदन समिति - बी. पट्टाभि सीतारमैया
- सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति - एस वरदाचारी
- वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति - नलिनी रंजन सरकार
- संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति - जवाहर लाल नेहरू
- भाषाई प्रांतों पर आयोग - एस.के. डार
- राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति - डॉ राजेंद्र प्रसाद

महत्वपूर्ण तिथियाँ

- 22 जुलाई 1947 - राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया
- मई 1949 - कॉमन वेल्थ सदस्यता
- 24 जनवरी 1950 - संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किये
- राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए
- आखिरी बैठक
- 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किये (15 महिलाएँ)

- संविधान निर्माता - अध्यक्ष - राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष - सच्चिदानंद सिन्हा, अध्यक्ष - जी.वी. मावलंकर
- कानून निर्माता - उपाध्यक्ष - वीटी कृष्णामाचारी और एचसी मुखर्जी
- कानूनी सलाहकार - बी एन राव
- मुख्य ड्राफ्ट्समैन - एसएन मुखर्जी

कार्य

- 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन लगा
- 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया
- 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया
- प्रतीक - हाथी
- सजावट - नंद लाल बोस, बेओहर राममनोहर सिन्हा
- सुलेख - प्रेम बिहारी नारायण रायजादा - अंग्रेजी, वसंत कुमार वैद्य - हिन्दी
- अंतिम ड्राफ्ट - 4 नवंबर 1948
- बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से बीआर अंबेडकर द्वारा

संविधान

- नागरिकता
- चुनाव
- अंतिम संसद

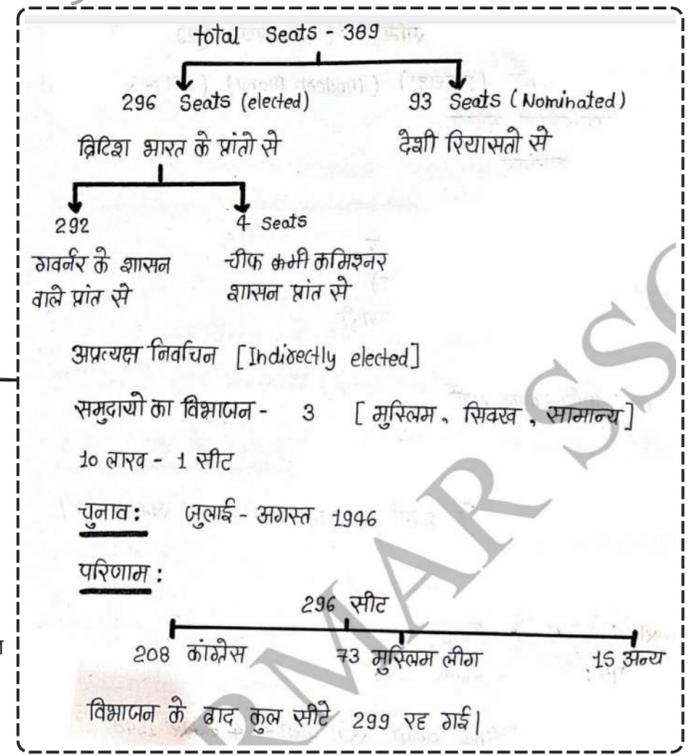
महत्वपूर्ण प्रारूप (ड्राफ्ट)

- 9-23 दिसम्बर 1946 - पहला ड्राफ्ट
- 6-17 अक्टूबर 1949 - 10वां ड्राफ्ट
- 14-26 नवम्बर 1949 - 11वां ड्राफ्ट
- 4 नवंबर 1948 - अंतिम ड्राफ्ट

प्रारूप समिति

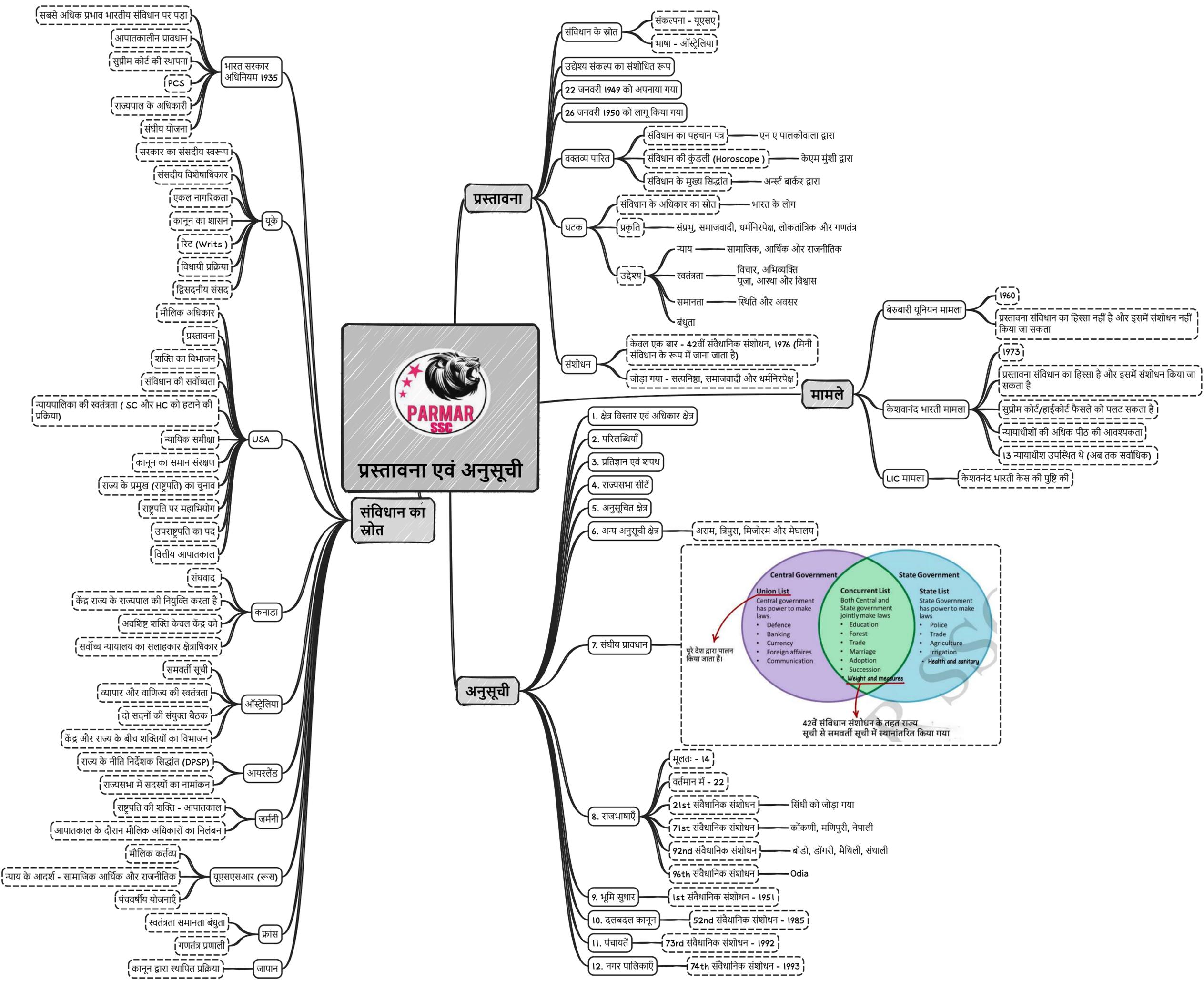
- 29 अगस्त 1947 को गठित
- भीम राव अम्बेडकर - अध्यक्ष
- अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
- एन गोपालस्वामी अय्यंगार
- मुहम्मद सादुल्लाह
- केएम मुंशी
- बीएल मित्र का स्थान एन. माधव राव ने लिया
- डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णामाचारी को दी गई

7 सदस्य

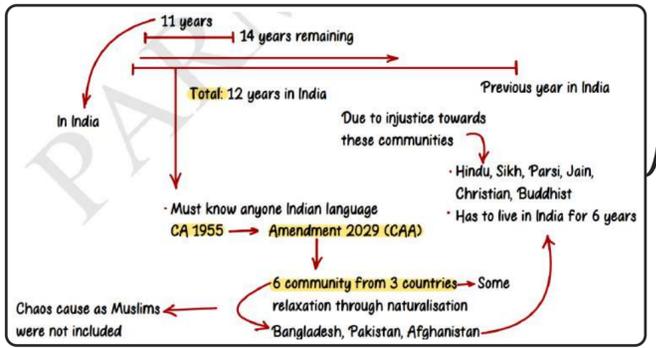
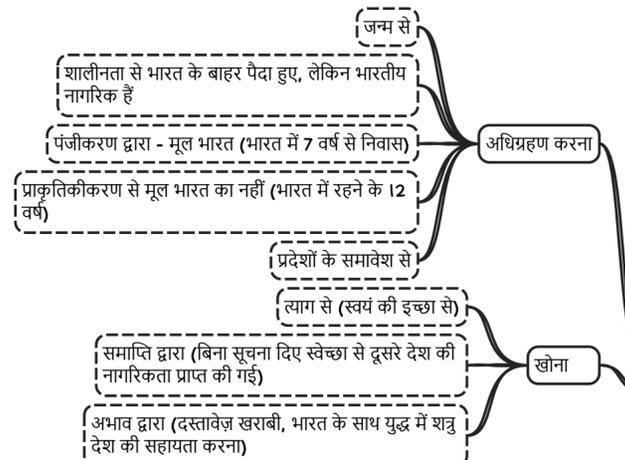




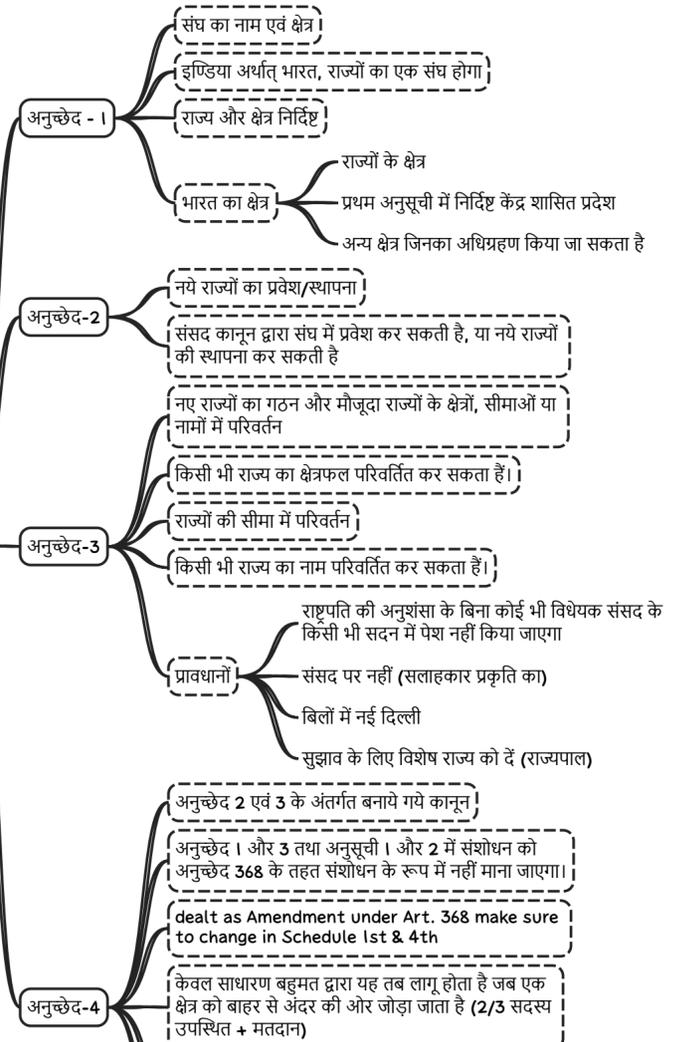
प्रस्तावना एवं अनुसूची



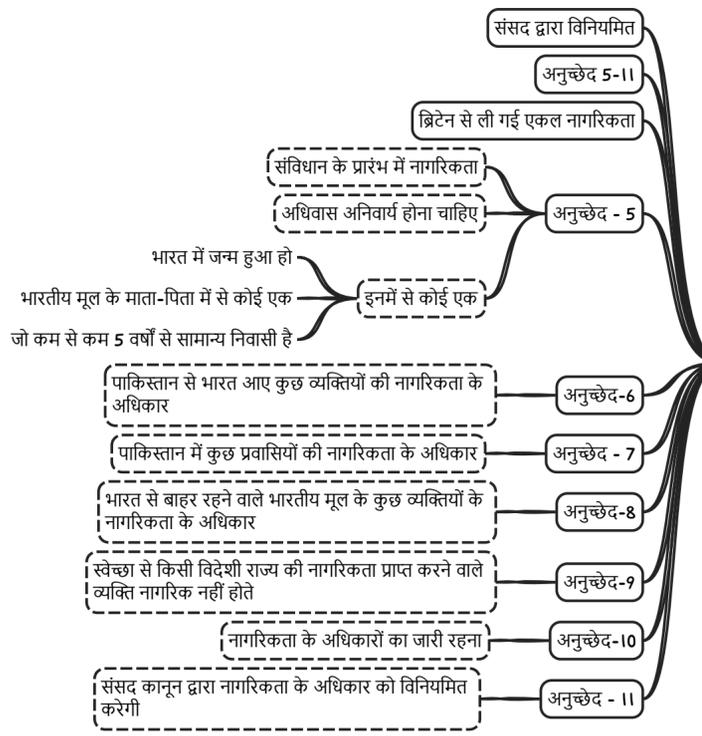
नागरिकता अधिनियम 1955



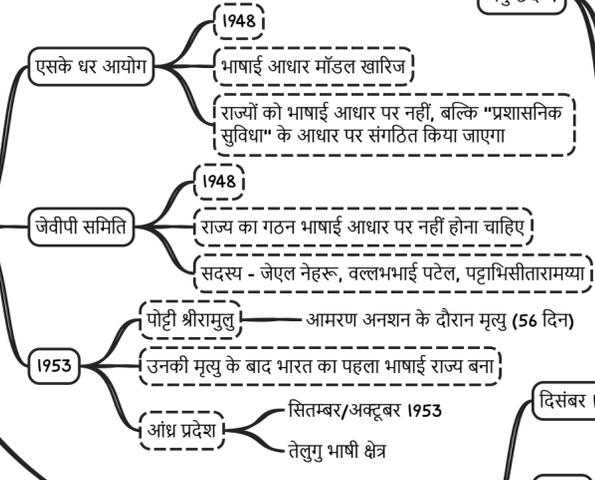
भाग-1 संघ एवं उसका क्षेत्र



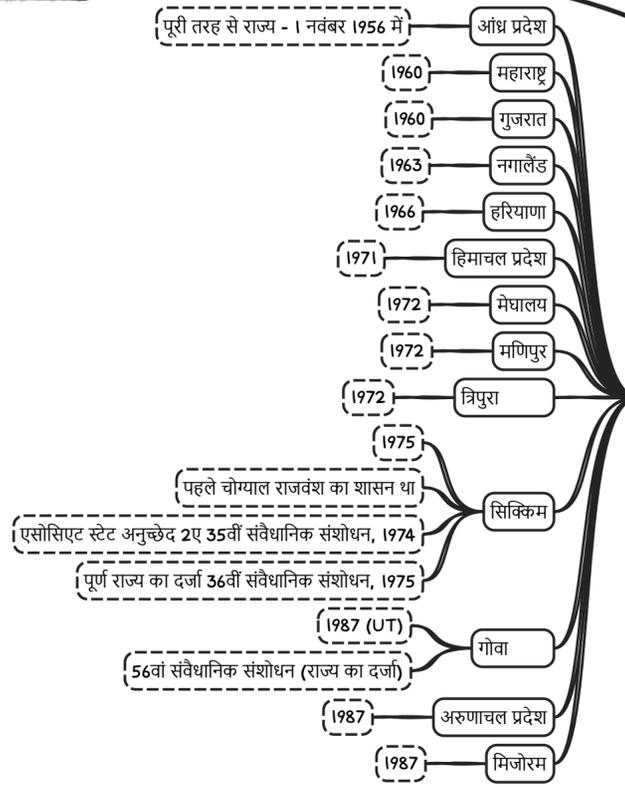
भाग-II नागरिकता



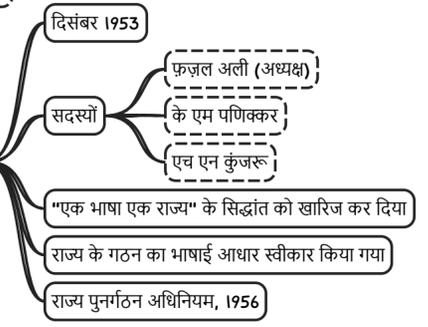
भाषाई प्रावधान आयोग



राज्यों का गठन



फ़ज़ल अली आयोग

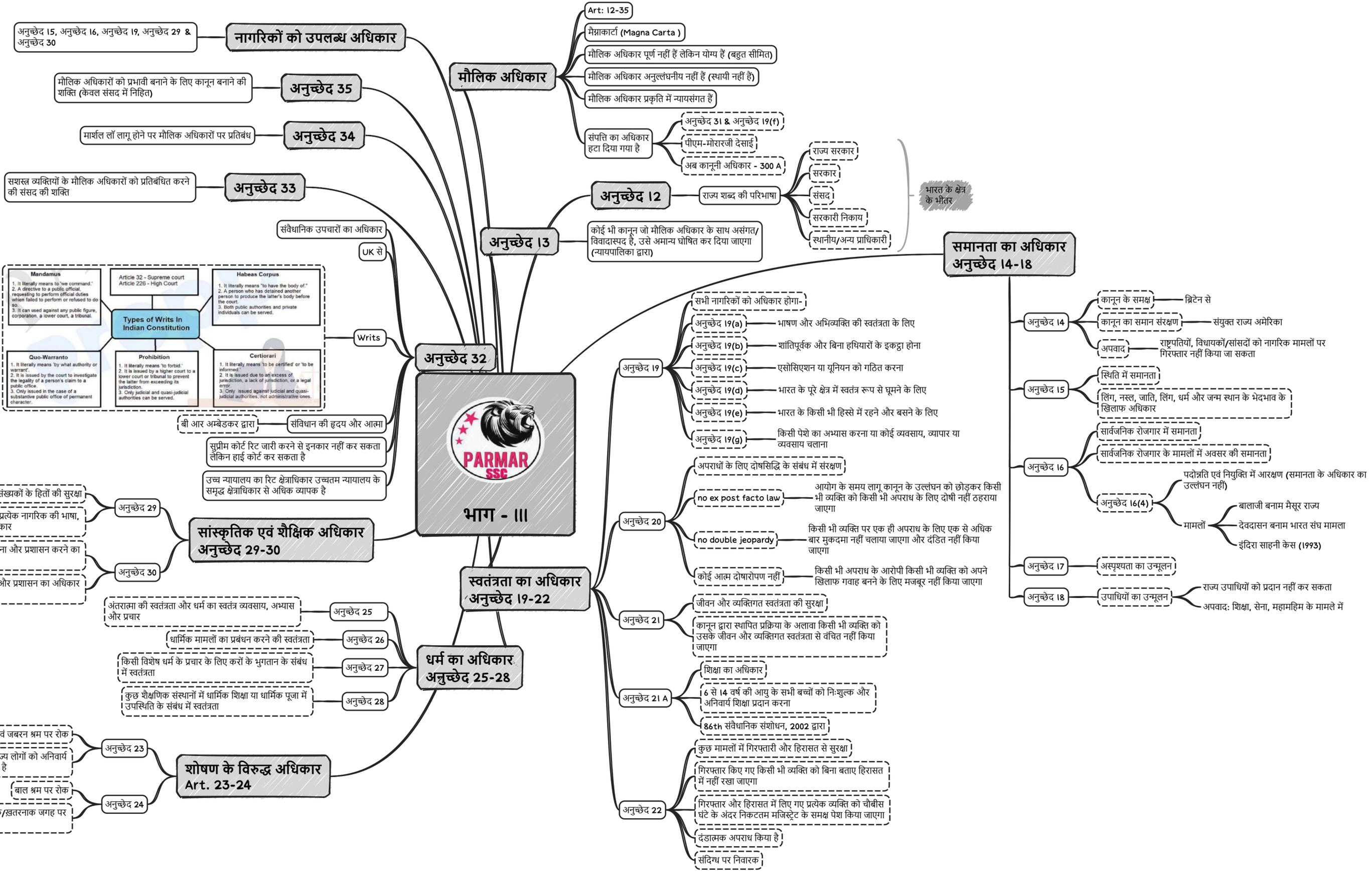


Article No.	Subject-matter
371	Special provision with respect to the states of Maharashtra and Gujarat.
371 - A.	Special provision with respect to the state of Nagaland.
371 - B.	Special provision with respect to the state of Assam
371 - C.	Special provision with respect to the state of Manipur
371 - D.	Special provisions with respect to the state of Andhra Pradesh or the state of Telangana
371 - E.	Establishment of Central University in Andhra Pradesh
371 - F.	Special provisions with respect to the state of Sikkim
371 - G.	Special provision with respect to the state of Mizoram
371 - H.	Special provision with respect to the state of Arunachal Pradesh
371 - I.	Special provision with respect to the state of Goa
371 - J.	Special provisions with respect to the state of Karnataka

विशेष शक्तियाँ



भाग - III





भाग - IV

DPSP

- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (Directive Principle Of The State Policy)
- आयरलैंड से लिया गया
- अनुच्छेद 36-51
- किसी भी कानून के संवैधानिक मूल्य की जांच करने के लिए

बयान

- संविधान की नवीन विशेषता (बीआर अंबेडकर द्वारा)
- संविधान की अंतरात्मा (ग्रेनविले ऑस्टिन द्वारा)
- भारत का संघवाद अर्ध-संघीय है (केसी व्हेयर द्वारा)
- DPSP बैंक पर चेक की तरह है जो बैंक की सहमति पर देय होता है (प्रोफेसर के.टी. द्वारा शाह)

अनुच्छेद 36

राज्य का अर्थ भाग-III के समान (अनुच्छेद 12)

अनुच्छेद 37

इस भाग में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा
गैर-न्यायसंगत हैं

अनुच्छेद 38

- राज्य सुरक्षा और संरक्षण द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगा
- राज्य द्वारा आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना (44th संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा)

अनुच्छेद 39

- अनुच्छेद 39(a) - आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार
- अनुच्छेद 39(b) - समुदाय के भौतिक संसाधनों को आम भलाई के लिए सर्वोत्तम तरीके से वितरित किया जाना
- अनुच्छेद 39(c) - आर्थिक व्यवस्था के संचालन से धन का संकेन्द्रण नहीं होता है
- अनुच्छेद 39(d) - पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन
- अनुच्छेद 39(e) - नागरिकों के स्वास्थ्य और ताकत का दुरुपयोग नहीं किया जाता है और आर्थिक आवश्यकता के कारण उन्हें उनकी उम्र या ताकत के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है
- अनुच्छेद 39(f) - Children - बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने, स्वतंत्रता और सम्मान के अवसर और सुविधाएं दिया जाना (42nd संवैधानिक संशोधन, 1976 द्वारा)

अनुच्छेद 39A

- राज्य गरीबों को न्याय सुनिश्चित करने के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून/योजनाओं के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा
- 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया

अनुच्छेद 40

राज्य ग्राम पंचायत की व्यवस्था करेगा उन्हें शक्तियाँ प्रदान करेगा

अनुच्छेद 41

- काम का अधिकार
- शिक्षा का अधिकार
- सार्वजनिक सहायता का अधिकार

बेरोजगारी, बुढ़ापा/बीमारी, और विकलांगता के मामलों में

अनुच्छेद 42

राज्य काम की मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा

अनुच्छेद 50

राज्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा

अनुच्छेद 49

राज्य कलात्मक/ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक, स्थान और वस्तु की रक्षा करेगा

अनुच्छेद 48A

राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करेगा
42nd संवैधानिक संशोधन, 1976 द्वारा

अनुच्छेद 48

- राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करेगा
- राज्य गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और माल देने वाले मवेशियों के वध पर रोक लगाएगा

अनुच्छेद 47

- राज्य पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने पर ध्यान देगा
- राज्य औषधीय प्रयोजन को छोड़कर नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा

अनुच्छेद 46

राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देगा

अनुच्छेद 45

- राज्य दस वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क देखभाल करने का प्रयास करेगा
- चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा (86th संवैधानिक संशोधन द्वारा)

अनुच्छेद 44

राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा

अनुच्छेद 43B

राज्य सहकारी समितियों के स्वेच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देगा
97th संवैधानिक संशोधन, 2011 द्वारा

अनुच्छेद 43A

राज्य किसी भी उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा
42nd संवैधानिक संशोधन, 1976 द्वारा

अनुच्छेद 43

- जीवनयापन लायक मजदूरी सुरक्षित करना
- जीवन का एक सभ्य मानक
- सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूरा आनंद
- राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा

अनुच्छेद 51

- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
- राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखना

मौलिक अधिकार v/s राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत



भाग - IV(A)

- चंपकम दोरैराजन मामला**
 - 1915
 - मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) पर प्रबल होंगे
 - मौलिक अधिकार संशोधन योग्य हैं
- गोलकनाथ केस**
 - 1967
 - संसद मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती
 - 24वाँ संवैधानिक संशोधन - संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है (संसद द्वारा)
 - 25वाँ संविधान संशोधन- कोई भी कानून जो अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) को लागू करने का प्रयास करता है, उसे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के आधार पर शून्य और अमान्य घोषित किया जाएगा
- केशवानंद भारती मामला**
 - 1973
 - 13 बेंच जजों का मामला
 - संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती
- मिनर्वल मिल मामला**
 - मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) के बीच आई बैलेंस की आधारशिला पर संवैधानिक पाया जाता है

मौलिक कर्तव्य

- यूएसएसआर (USSR) से लिया गया
- सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
- 10 कर्तव्य (42nd संवैधानिक संशोधन द्वारा)
- 11th मौलिक कर्तव्य - 51 (k) (86th संवैधानिक संशोधन द्वारा)
- केवल भारतीयों के लिए लागू

अनुच्छेद 51A (a)

संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना

अनुच्छेद 51A (b)

उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया

अनुच्छेद 51A (c)

भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए

अनुच्छेद 51A (d)

देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना

अनुच्छेद 51A (e)

भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना

महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना

अनुच्छेद 51A (f)

हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना

अनुच्छेद 51A (g)

प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना

जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना

अनुच्छेद 51A (k)

माता-पिता, अभिभावक द्वारा अपने बच्चे (6-14 वर्ष की आयु के बीच) को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।

अनुच्छेद 51A (j)

व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना

अनुच्छेद 51A (i)

सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना

अनुच्छेद 51A (h)

वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना



भाग - V

The Union

- अध्याय 1 - कार्यकारी
- अध्याय 2 - संसद
- अध्याय 3 - राष्ट्रपति की विधायी शक्ति
- अध्याय 4 - संघ न्यायपालिका
- अध्याय 5 - भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

The Union Executive

- भारतीय संघ के प्रमुख
- भारत का प्रथम नागरिक

अनुच्छेद 52

- भारत के राष्ट्रपति
- भारत का एक राष्ट्रपति होगा

अनुच्छेद 54

अनुच्छेद 53

- संघ की कार्यकारी शक्ति
- संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी
- संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी

अनुच्छेद 55

- राष्ट्रपति का चुनाव
- राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा
- संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा (सभी निर्वाचित सांसद एवं विधायक)
- राष्ट्रपति के चुनाव की रीति
- अप्रत्यक्ष चुनाव (राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति)
- आनुपातिक प्रतिनिधि + एकल हस्तांतरणीय वोट
- गुप्त मतपत्र द्वारा

50 proposers + 50 seconders - President elections

Quota = $\frac{\text{Total votes}}{\text{No. of Candidates} + 1} + 1$

Value of vote of all MLAs = $\frac{\text{Total population of State} \times 1}{\text{No. of elected MLA} \times 1000}$

Value of vote of MP = $\frac{\text{Total value of votes of all MLAs}}{\text{Total no. of elected MPs}}$

अनुच्छेद 56

- राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल
- राष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर
- उपराष्ट्रपति को इस्तीफा

अनुच्छेद 57

- पुनः चुनाव के लिए पात्रता
- उस कार्यलय के लिए पुनः चुनाव के लिए पात्र

अनुच्छेद 61

- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
- संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना है
- आरोप को संसद के किसी भी सदन द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी
- ऐसा प्रस्ताव कम से कम 14 दिनों के लिखित नोटिस के बाद पेश किया गया है
- सदन के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित
- ऐसा प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया है

अनुच्छेद 72

- क्षमादान देने की राष्ट्रपति की शक्ति
- राष्ट्रपति के पास सजा को क्षमा करने, राहत देने, राहत देने या कम करने या सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की शक्ति होगी।
- मौत की सजा माफ कर सकता है

अनुच्छेद 62

- राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा
- रिक्ति भरने के लिए चुनाव
- मृत्यु, इस्तीफा या निष्कासन के मामले में - उपराष्ट्रपति, CJI या SC के न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे

अनुच्छेद 60

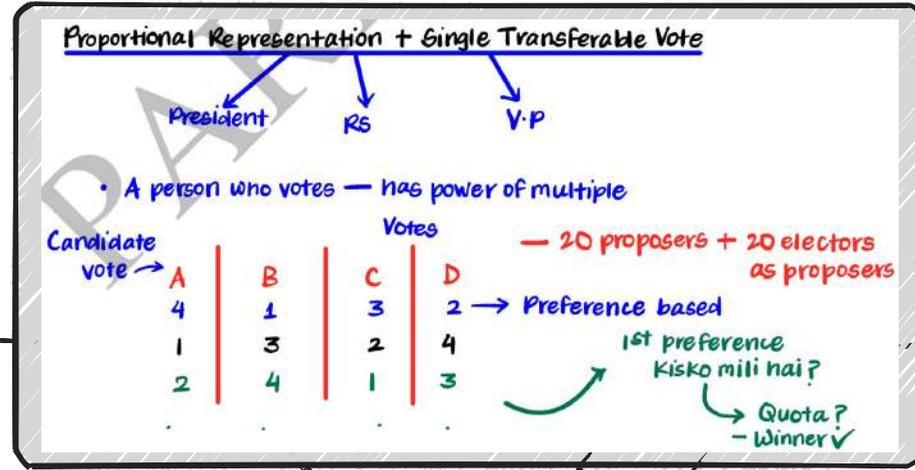
- राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में सदस्यता लेंगे
- या, उसकी अनुपस्थिति में, उपलब्ध उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश

अनुच्छेद 59

- राष्ट्रपति कार्यलय की शर्तें
- राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा
- राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किये जायेंगे

अनुच्छेद 58

- राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ
- भारत का नागरिक
- पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर ली
- लोक सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र
- भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो



अनुच्छेद 71

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी चुनावी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा

अनुच्छेद 63

भारत के उपराष्ट्रपति

भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा.

अनुच्छेद 70

अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन

अनुच्छेद 64

उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा

लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा

अनुच्छेद 69

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान.

प्रत्येक उपराष्ट्रपति, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर करेगा

अनुच्छेद 65

उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना



अनुच्छेद 68

उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय

किसी रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा

उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण उनके पद पर हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव 60 दिनों के भीतर होगा।

अनुच्छेद 66

उपराष्ट्रपति का चुनाव

उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों (सभी सांसद) द्वारा किया जाएगा।

आनुपातिक प्रतिनिधि + एकल हस्तांतरणीय वोट

उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा

उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्रता

- भारत का नागरिक
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो
- राज्य सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य

भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए

अनुच्छेद 67

उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल

उपराष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा

राष्ट्रपति को इस्तीफा

किसी उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोक सभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।

एक उपराष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी उसके कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेता

